Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 1 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

करनाल मंडल की कृषि संरचना और संस्थागत कृषि ऋण की भूमिकाः एक सामाजिक–आर्थिक अध्ययन

[1]राजेश कुमार, [2]डॉ. प्रदीप कुमार

[1]शोधार्थी, [2]पर्यवेक्षक

विभाग : अर्थशास्त्र, एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय, कैथल

सार

यह शोध–पत्र करनाल मंडल अर्थात् करनाल, पानीपत, कैथल और कुरुक्षेत्र की कृषि संरचना तथा संस्थागत कृषि ऋण की प्रवृत्तियों का सामाजिक–आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करता है। अध्ययन का मूल उद्देश्य यह समझना है कि इस मंडल की कृषि व्यवस्था, सिंचाई–आधार, फसल–प्रधानता, बाजार–संबद्धता और औपचारिक वित्त तक पहुँच के बीच किस प्रकार का संबंध है। संशोधित संस्करण में शोध–पत्र के सभी अपेक्षित घटक सार, प्रस्तावना, उद्देश्य, शोध–पद्धति, द्वितीयक आँकड़ों की सारणी, विश्लेषण, निष्कर्ष एवं सुझाव समुचित रूप से जोड़े गए हैं। अध्ययन में उपलब्ध सरकारी एवं संस्थागत द्वितीयक स्रोतों, जैसे हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति हरियाणा दस्तावेज, भारत सरकार के कृषि ऋण सम्बन्धी प्रकाशन तथा एसबीआई के वार्षिक प्रतिवेदनों का उपयोग किया गया है। हालिया जिला–स्तरीय केसीसी कृषि ऋण आँकड़े यह संकेत देते हैं कि करनाल मंडल के भीतर भी औपचारिक कृषि ऋण की पहुँच समान नहीं है। करनाल में केसीसी खातों की संख्या में तीव्र वृद्धि दिखाई देती है, जबकि पानीपत में सीमित किन्तु सकारात्मक विस्तार दर्ज होता है; दूसरी ओर कैथल और कुरुक्षेत्र में खातों की वृद्धि के बावजूद औसत ऋण–गहराई में दबाव दिखाई देता है। अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि करनाल मंडल की कृषि संरचना, जो हरित क्रांति–उत्तर सिंचित, बाजारोन्मुख और उच्च इनपुट–आधारित कृषि पर आधारित है, उसे स्थायी रूप से समर्थन देने हेतु संस्थागत ऋण का

विस्तार केवल मात्रा के आधार पर पर्याप्त नहीं है। समयबद्ध, फसल–विशिष्ट, छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए अधिक लचीला, डिजिटल रूप से सुगम तथा निवेश–उन्मुख कृषि ऋण ढाँचा आवश्यक है।

मुख्य भाब्दः करनाल मंडल, कृषि संरचना, संस्थागत कृषि ऋण, सामाजिक–आर्थिक अध्ययन, गेहूँ–धान प्रणाली, बासमती धान, कृषि यंत्रीकरण, पूँजीगत आवश्यकता।

1. प्रस्तावना

भारतीय कृषि केवल उत्पादन की गतिविधि नहीं, बल्कि ग्रामीण समाज, आजीविका, रोजगार, बाजार, उपभोग और सामाजिक संरचना का आधार है। हरियाणा इस संदर्भ में विशेष महत्व रखता है क्योंकि हरित क्रांति के बाद यहाँ की कृषि ने देश की खाद्य–सुरक्षा में असाधारण योगदान दिया। करनाल मंडल, जिसमें करनाल, पानीपत, कैथल और कुरुक्षेत्र शामिल हैं, पूर्वी हरियाणा के उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ सिंचाई, उन्नत बीज, यंत्रीकरण, मंडी–व्यवस्था तथा गेहूँ–धान प्रधान कृषि प्रणाली ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संरचित किया ळें ऐसी कृषि व्यवस्था में ऋण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्नत कृषि निवेश – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, मशीनरी, फसल–परिवहन, भंडारण तथा फसलोत्तर गतिविधियों के लिए पूँजी की नियमित आवश्यकता होती है। यदि यह पूँजी समय पर औपचारिक संस्थानों से उपलब्ध नहीं होती, तो किसान अनौपचारिक साहूकारी तंत्र की ओर धकेले जाते हैं, जिससे ब्याज–बोझ, ऋणग्रस्तता और आय–असुरक्षा बढ़ती है।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रामीण जीवन, रोजगार, आय और सामाजिक संरचना का प्रमुख आधार खेती तथा उससे संबंधित गतिविधियाँ होती हैं। हरियाणा राज्य का करनाल मंडल ऐसा ही एक कृषि–प्रधान क्षेत्र है, जिसने हरित क्रांति, सिंचाई सुविधाओं, उन्नत बीजों, यंत्रीकरण और बाजारोन्मुख उत्पादन के माध्यम से

कृषि विकास का एक विशिष्ट मॉडल प्रस्तुत किया है। इस क्षेत्र में गेहूँ–धान आधारित फसल प्रणाली, बासमती धान की व्यावसायिक खेती, कृषि विपणन तंत्र, परिवहन सुविधा तथा बैंकिंग नेटवर्क की उपलब्धता ने कृषि को केवल जीविकोपार्जन का साधन न रहने देकर आय, निवेश और आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बना दिया है। किंतु आधुनिक कृषि के इस विकसित स्वरूप के साथ लागत में वृद्धि, पूँजीगत आवश्यकता, जोतों का विखंडन, बाजार जोखिम तथा ऋण पर बढ़ती निर्भरता जैसी चुनौतियाँ भी उभरी हैं। विशेष रूप से लघु और सीमांत कृषकों के लिए संस्थागत ऋण की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि इसके बिना वे आधुनिक कृषि निवेशों का वहन नहीं कर सकते।

इसी पृष्ठभूमि में संस्थागत कृषि ऋण–विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, केसीसी व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ग्रामीण विकास के केंद्रीय उपकरण बन जाते हैं। एसबीआई, देश का सबसे बड़ा बैंक होने के कारण, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः करनाल मंडल की कृषि संरचना का अध्ययन, संस्थागत ऋण की उपलब्धता और उसकी प्रवृत्तियों को समझे बिना अधूरा है।

2. अध्ययन की आवश्यकता और औचित्य

करनाल मंडल की कृषि सामान्यतः समृद्ध, सिंचित और बाजार–संलग्न मानी जाती है; किंतु इसी धारणा के भीतर कई महत्वपूर्ण अंतर्विरोध भी मौजूद हैं। पहली दृष्टि में यह क्षेत्र कृषि ऋण के लिए अपेक्षाकृत उन्नत प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ फसल विविधता सीमित होने पर भी नकद–निवेश की तीव्रता अधिक है। परंतु गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि कृषि ऋण की उपलब्धता, उपयोग, पुनर्भुगतान क्षमता और ऋण–गहराई सभी जिलों में समान नहीं है। विश्वविद्यालयीय संशोधन की दृष्टि से यह शोध–पत्र इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि मूल ड्राफ्ट में सार, भूमिका, उद्देश्य, कार्यविधि, सारणीबद्ध द्वितीयक आँकड़े, सुझाव तथा संरचित निष्कर्ष जैसे

अनिवार्य भाग अधूरे थे। वर्तमान संशोधित संस्करण में इन्हें व्यवस्थित रूप से जोड़ा गया है ताकि शोध–पत्र अकादमिक मानकों के अनुरूप प्रस्तुत किया जा सके। इस अध्ययन का एक और महत्त्व यह है कि यह केवल ऋण–वितरण की मात्रा पर नहीं, बल्कि कृषि संरचना और ऋण के परस्पर संबंध पर बल देता है। प्रश्न यह नहीं है कि केवल कितना ऋण दिया गया, बल्कि यह भी है कि किस प्रकार की कृषि व्यवस्था में किस प्रकार का ऋण अधिक उपयोगी, न्यायोचित और स्थायी सिद्ध होता है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

1. करनाल मंडल की कृषि संरचना की प्रमुख विशेषताओं–फसल–प्रधानता, सिंचाई, निवेश–आधार और बाजार–संबद्धता–का विश्लेषण करना।

2. संस्थागत कृषि ऋण की अवधारणा, आवश्यकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका का परीक्षण करना।

3. एसबीआई के कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित समष्टिगत ऋण–पोर्टफोलियो में हालिया परिवर्तन को समझना।

4. करनाल, पानीपत, कैथल और कुरुक्षेत्र जिलों में उपलब्ध द्वितीयक केसीसीध्कृषि ऋण संकेतकों का तुलनात्मक विश्लेषण करना।

5. कृषि संरचना और औपचारिक ऋण पहुँच के बीच संबंध स्थापित करना।

6. छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए अधिक प्रभावी, समावेशी और फसल–उपयुक्त ऋण नीति संबंधी सुझाव प्रस्तुत करना।

4. शोध–पद्धति

4.1 अध्ययन का स्वरूप

यह अध्ययन वर्णनात्मकएवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें प्राथमिक सर्वेक्षण के बजाय द्वितीयक आँकड़ों, नीतिगत दस्तावेजों, आर्थिक सर्वेक्षणों, बैंकिंग प्रतिवेदनों तथा कृषि–वित्त संबंधी प्रकाशनों का उपयोग किया गया है। अध्ययन की इकाई करनाल मंडल है, जिसके अंतर्गत करनाल, पानीपत, कैथल एवं कुरुक्षेत्र जिलों को शामिल किया गया है।

4.2 डेटा के स्रोत

अध्ययन में उपयोग किए गए प्रमुख द्वितीयक स्रोत हैंः (1) हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 और 2024–25, (2) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति हरियाणा की बैठक–सामग्री एवं वार्षिक ऋण योजना से संबंधित आँकड़े, (3) भारत सरकार के कृषि ऋण–ग्राउंड लेवल क्रेडिट संबंधी प्रतिवेदन, (4) एसबीआई के वार्षिक प्रतिवेदन 2022–23 और 2023–24, तथा (5) हरियाणा में जिला–स्तरीय औपचारिक कृषि ऋण पहुँच पर उपलब्ध हालिया शोध–आधारित संकलित आँकड़े।

4.3 अध्ययन की अवधि

मूल संशोधन–निर्देश में 2011 से 2024 तक एसबीआई द्वारा दिए गए ऋण की जिला–वार शृंखला जोड़ने की अपेक्षा की गई थी। उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों की जाँच के बाद यह पाया गया कि इस सम्पूर्ण अवधि के लिए करनाल मंडल का एसबीआई–विशिष्ट, जिला–वार, वार्षिक कृषि ऋण डेटा सार्वजनिक डोमेन में एकसमान रूप से उपलब्ध नहीं है। अतः इस संशोधित संस्करण में उपलब्ध, सत्यापित तथा अकादमिक उपयोग योग्य हालिया श्रृंखलाओं का उपयोग किया गया है, और जहाँ–जहाँ प्रत्यक्ष शृंखला उपलब्ध नहीं है वहाँ यह सीमा स्पष्ट रूप से बताई गई है।

4.4 विश्लेषण की तकनीक

विश्लेषण हेतु तुलनात्मक पद्धति, प्रतिशत परिवर्तन, उपलब्ध ऋण–गहराई की व्याख्या, तथा प्रसंगानुकूल वर्णनात्मक विश्लेषण का उपयोग किया गया है। जहाँ संभव हुआ, वहाँ सारणीबद्ध प्रस्तुति के माध्यम से समयानुसार परिवर्तन को दिखाया गया है; और जहाँ पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध नहीं थी, वहाँ संस्थागत रुझानों के आधार पर व्याख्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

5. करनाल मंडल का भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिचय

करनाल मंडल हरियाणा के उन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कृषि विकास के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती हैं। इस क्षेत्र की स्थलाकृति मुख्यतः समतल है, जिससे सिंचाई, जुताई, मशीनों के उपयोग तथा कृषि कार्यों के प्रबंधन में सुविधा होती है। यहाँ की मृदा प्रायः उपजाऊ दोमट प्रकृति की है, जो धान, गेहूँ, गन्ना तथा अन्य खाद्यान्न एवं वाणिज्यिक फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जलवायु भी सामान्यतः कृषि के अनुकूल है, यद्यपि वर्षा की मात्रा और उसका समय कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। फिर भी नहरों, नलकूपों और भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग ने इस क्षेत्र में सिंचाई का अपेक्षाकृत सुदृढ़ आधार विकसित किया है, जिसके कारण कृषि उत्पादन में स्थिरता बनी रहती है। यही कारण है कि करनाल मंडल को हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था का एक सशक्त क्षेत्र माना जाता है (हरियाणा सरकार, 2024,नाबार्ड, 2022)।

सामाजिक दृष्टि से करनाल मंडल की संरचना ग्रामीण जीवन और कृषि गतिविधियों से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष रूप से खेती करती है, जबकि शेष आबादी कृषि से संबंधित सहायक कार्यों–जैसे पशुपालन, डेयरी, मजदूरी, व्यापार, परिवहन, कृषि आदानों की आपूर्ति और मंडी–आधारित सेवाओं–से जुड़ी रहती है। इस प्रकार कृषि केवल उत्पादन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक आय, श्रम संबंधों और ग्रामीण

जीवन–पद्धति का आधार है। करनाल मंडल में धान–गेहूँ आधारित फसल प्रणाली विशेष रूप से प्रचलित है, जिसने क्षेत्र को उच्च कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्रों में स्थान दिलाया है। विशेष रूप से बासमती धान की खेती ने इस क्षेत्र की एक विशिष्ट पहचान बनाई है, क्योंकि इसके माध्यम से स्थानीय कृषि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ती है। इससे किसानों की आय के अवसर बढ़ते हैं और क्षेत्र की कृषि को व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त होता है (भारद्वाज, 2019, सिंह एवं कुमार, 2018)।

आर्थिक दृष्टि से करनाल मंडल की कृषि अपेक्षाकृत विकसित, वाणिज्यिक और निवेश उन्मुख दिखाई देती है। इस क्षेत्र में मंडियों, सड़कों, परिवहन सुविधाओं, भंडारण संरचनाओं और कृषि विपणन तंत्र की उपलब्धता ने कृषि को बाजार से घनिष्ठ रूप से जोड़ दिया है। किसान अपनी उपज को आसानी से बाजार तक पहुँचा सकते हैं, जिससे कृषि केवल आत्मनिर्वाह का साधन न रहकर आय और विनिमय का प्रमुख माध्यम बन गई है। साथ ही, आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि यंत्रों और सिंचाई उपकरणों के बढ़ते उपयोग ने उत्पादन क्षमता को तो बढ़ाया है, परंतु कृषि लागत में भी निरंतर वृद्धि की है। डीजल, बिजली, श्रम, मशीनरी तथा अन्य कृषि निवेशों पर बढ़ते व्यय ने किसानों की पूँजीगत आवश्यकता को पहले की तुलना में अधिक बढ़ा दिया है। परिणामस्वरूप करनाल मंडल की कृषि व्यवस्था अब काफी हद तक ऋण–आधारित और संस्थागत वित्त पर निर्भर होती जा रही है (लता, 2016, नाबार्ड, 2022)।

इसी परिप्रेक्ष्य में करनाल मंडल में बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। कृषि उत्पादन की निरंतरता, आधुनिक तकनीकों के उपयोग, कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई निवेश तथा पशुपालन और डेयरी जैसी सहायक गतिविधियों के विस्तार के लिए किसानों को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। यदि यह सहायता संस्थागत माध्यमों से उपलब्ध न हो, तो किसान गैर–संस्थागत स्रोतों पर निर्भर होने के लिए विवश हो सकते हैं, जिससे

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 1 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय स्टेट बैंक जैसी बैंकिंग संस्थाएँ इस क्षेत्र में किसानों को उत्पादन ऋण, निवेश ऋण, कृषि यंत्रों हेतु ऋण तथा अन्य वित्तीय सुविधाएँ प्रदान कर कृषि विकास को गति देती हैं। अतः करनाल मंडल का भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि यह क्षेत्र न केवल कृषि संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि कृषि वित्त और ग्रामीण विकास के अध्ययन के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है।

5.1 करनाल मंडल की कृषि संरचना

करनाल मंडल की कृषि संरचना हरियाणा की विकसित कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, सिंचाई सुविधाओं, उन्नत कृषि तकनीकों, बाजार से जुड़ाव तथा संस्थागत वित्त की उपलब्धता के कारण राज्य के अग्रणी कृषि क्षेत्रों में गिना जाता है। फिर भी इसकी कृषि संरचना केवल समृद्धि का चित्र प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि इसमें जोतों के आकार, लागत दबाव, जोखिम, पूँजीगत आवश्यकताओं तथा कृषक वर्गों के बीच असमानताओं जैसे कई आयाम भी सम्मिलित हैं। इसलिए करनाल मंडल की कृषि संरचना का अध्ययन केवल फसल उत्पादन के आधार पर नहीं, बल्कि भूमि व्यवस्था, तकनीकी स्वरूप, पूँजी निवेश, जोखिम तथा कृषि वित्त के व्यापक संदर्भ में किया जाना चाहिए।

1 जोतों का स्वरूप और कृषक वर्ग

करनाल मंडल की कृषि संरचना का पहला महत्त्वपूर्ण पक्ष जोतों का स्वरूप है। इस क्षेत्र में बड़े, मध्यम, लघु तथा सीमांत सभी प्रकार के कृषक पाए जाते हैं। यद्यपि हरित क्रांति के प्रभाव, सिंचाई उपलब्धता तथा उच्च उत्पादकता ने इस क्षेत्र को समृद्ध कृषि क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है, फिर भी भूमि स्वामित्व का वितरण समान नहीं है। बड़े और मध्यम कृषकों के पास अपेक्षाकृत अधिक भूमि, पूँजी और संसाधन उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण वे आधुनिक तकनीकों और बाजार अवसरों का लाभ अधिक कुशलता से उठा पाते हैं। इसके विपरीत लघु और सीमांत

कृषकों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि उनके पास भूमि का आकार छोटा होता है, निवेश क्षमता सीमित होती है और जोखिम वहन करने की शक्ति कम होती है।

भूमि जोतों का विखंडन इस क्षेत्र की कृषि संरचना को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख तत्व है। पीढ़ी–दर–पीढ़ी भूमि के विभाजन के कारण अनेक कृषकों की जोतें छोटी होती गई हैं। छोटी जोतों पर यंत्रीकरण, आधुनिक तकनीकों का पूर्ण उपयोग तथा व्यावसायिक कृषि का विस्तार अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। इससे उत्पादन लागत प्रति इकाई अधिक महसूस होती है और लाभांश कम हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में लघु एवं सीमांत किसान अक्सर ऋण पर अधिक निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कृषि निवेश के लिए पर्याप्त स्वनिधि उपलब्ध नहीं होती (सिंह एवं कुमार, 2018, कुमार एवं सिंह, 2021)।

2 फसल प्रतिरूप और उत्पादन प्रणाली

करनाल मंडल की कृषि संरचना में फसल प्रतिरूप का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में गेहूँ–धान प्रणाली का स्पष्ट प्रभुत्व दिखाई देता है, जो हरियाणा की व्यापक कृषि संरचना से भी मेल खाता है। धान और गेहूँ की यह दो–फसली प्रणाली क्षेत्र की सिंचाई उपलब्धता, उपजाऊ भूमि, सरकारी खरीद व्यवस्था तथा मंडी ढाँचे के कारण लंबे समय से स्थापित है। इस प्रणाली ने क्षेत्र को उच्च कृषि उत्पादकता वाला स्वरूप प्रदान किया है और किसानों को अपेक्षाकृत स्थिर विपणन अवसर भी उपलब्ध कराए हैं।

इसके अतिरिक्त करनाल मंडल के कुछ क्षेत्रों में बासमती धान की खेती विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। बासमती उत्पादन ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा है, जिससे कृषि का वाणिज्यिक स्वरूप और अधिक मजबूत हुआ है। बासमती जैसी नकदी–उन्मुख फसलें किसानों को अधिक आय की संभावना प्रदान करती हैं, परंतु साथ ही इनमें बाजार मूल्य के उतार–चढ़ाव का जोखिम भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसके अलावा चारा फसलें, सब्जियाँ

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed
Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 1 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

तथा पशुपालन और डेयरी जैसी सहायक गतिविधियाँ भी कृषि संरचना को पूरक आधार प्रदान करती हैं। इस प्रकार करनाल मंडल की कृषि संरचना केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुआयामी ग्रामीण उत्पादन प्रणाली के रूप में विकसित हुई है (अरोड़ा एवं ज्योति, 2022, चहल एवं रानी, 2021)।

3 कृषि का तकनीकी एवं यंत्रीकृत स्वरूप

करनाल मंडल की कृषि संरचना का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष इसका उच्च तकनीकी और यंत्रीकृत स्वरूप है। इस क्षेत्र में ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, लेजर लेवलर, हैप्पी सीडर, ट्यूबवेल तथा अन्य कृषि यंत्रों का व्यापक उपयोग किया जाता है। आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग ने उत्पादन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, तीव्र और श्रम–कुशल बनाया है। समय पर जुताई, बुवाई, सिंचाई और कटाई की सुविधा ने उत्पादकता वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा कृषि यंत्रों के प्रयोग से जहाँ उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, वहीं कृषि की पूँजीगत प्रकृति भी अधिक गहरी हुई है। अब कृषि केवल श्रम और भूमि पर आधारित गतिविधि नहीं रह गई, बल्कि यह ऐसी आर्थिक प्रक्रिया बन गई है जिसमें मशीनरी, ऊर्जा, आधुनिक आदान और तकनीकी प्रबंधन का लगातार बढ़ता हुआ योगदान है। इस परिवर्तन ने किसानों की पूँजीगत आवश्यकताओं को बढ़ाया है और कृषि को ऋण–निर्भर बनाने में भी भूमिका निभाई है। विशेष रूप से लघु और सीमांत कृषकों के लिए इन आधुनिक साधनों का वहन करना बिना बाहरी वित्तीय सहायता के कठिन हो जाता है (अरोड़ा एवं ज्योति, 2022)।

4 पूँजीगत आवश्यकता और लागत संरचना

करनाल मंडल की कृषि संरचना में लागत का बढ़ता स्वरूप एक केंद्रीय विशेषता बन चुका है। आधुनिक कृषि पद्धतियों के कारण बीज, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल, बिजली, सिंचाई, मशीन किराया, मजदूरी तथा फसल कटाई–पश्चात क्रियाओं पर होने वाला व्यय लगातार बढ़ रहा है। विशेष रूप से धान और गेहूँ जैसी उच्च निवेश वाली फसलों के लिए समय पर पूँजी उपलब्ध होना आवश्यक हो जाता है। यदि किसान के पास पर्याप्त पूँजी न हो, तो वह या तो आवश्यक कृषि निवेश कम कर देता है या फिर ऋण लेने के लिए विवश होता है।

यह स्थिति इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि करनाल मंडल की कृषि संरचना स्वयं ऐसी है जो ऋण की मांग उत्पन्न करती है। उत्पादन ऋण की आवश्यकता खेती के मौसमी कार्यों के लिए होती है, जबकि निवेश ऋण की आवश्यकता कृषि यंत्रों, सिंचाई साधनों, पशुपालन, डेयरी तथा अन्य कृषि–सहायक गतिविधियों के लिए पड़ती है। बड़े कृषक अपनी बचत या परिसंपत्तियों के आधार पर इन लागतों को कुछ हद तक वहन कर सकते हैं, परंतु लघु और सीमांत किसानों के लिए संस्थागत ऋण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अतः इस क्षेत्र की कृषि संरचना को समझने के लिए लागत और पूँजी की भूमिका को केंद्र में रखना अनिवार्य है (कुमार एवं सिंह, 2021, चहल एवं रानी, 2021)।

5 कृषि जोखिम और संरचनात्मक चुनौतियाँ

यद्यपि करनाल मंडल की कृषि उन्नत और उत्पादक मानी जाती है, फिर भी यह पूर्णतः जोखिम–मुक्त नहीं है। कृषि संरचना का एक महत्त्वपूर्ण तत्व जोखिम है, जो प्राकृतिक, तकनीकी और बाजार संबंधी रूपों में विद्यमान रहता है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, तापमान में असामान्य परिवर्तन, फसल रोग, कीट प्रकोप तथा जल उपलब्धता में असंतुलन उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार मूल्य में उतार–चढ़ाव और लागत में वृद्धि किसानों की शुद्ध आय को कम कर सकती है।

विशेष रूप से उन किसानों के लिए यह जोखिम अधिक गंभीर हो जाता है जो ऋण लेकर खेती करते हैं। यदि उत्पादन प्रभावित होता है या बाजार मूल्य कम मिलते हैं, तो उनकी पुनर्भुगतान क्षमता कमजोर हो सकती है। इस स्थिति में कृषि केवल उत्पादन की प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि वह जोखिम प्रबंधन, लागत संतुलन और वित्तीय स्थिरता का प्रश्न भी बन जाती है। इसलिए करनाल मंडल की कृषि संरचना का मूल्यांकन करते समय यह समझना आवश्यक है कि यहाँ कृषि विकास के साथ–साथ जोखिम की गहनता भी विद्यमान है (सैनी एवं सिंह, 2017, सिंह एवं प्रकाश, 2021)।

6 कृषि संरचना और ऋण की आवश्यकता

करनाल मंडल की कृषि संरचना का समग्र विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि यह क्षेत्र उच्च उत्पादकता, उन्नत तकनीक और बाजार संपर्क के कारण विकसित कृषि क्षेत्र अवश्य है, परंतु इसकी कृषि व्यवस्था ऋण–सापेक्ष भी है। यहाँ ऋण की आवश्यकता केवल पूँजी की कमी के कारण नहीं, बल्कि कृषि की संरचनात्मक प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है। उच्च निवेश वाली खेती, दो–फसली प्रणाली, यंत्रीकरण, सिंचाई साधनों का रख–रखाव, पशुपालन, डेयरी और बाजारोन्मुख उत्पादन–ये सभी तत्व किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं।

इस दृष्टि से केवल ऋण वितरण पर्याप्त नहीं माना जा सकता। ऋण का समय पर उपलब्ध होना, आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में मिलना, उसका उत्पादक उपयोग सुनिश्चित होना तथा पुनर्भुगतान के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित होना भी समान रूप से आवश्यक है। इसलिए करनाल मंडल की कृषि संरचना का अध्ययन सीधे–सीधे कृषि वित्त और बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका से जुड़ जाता है। यही वह आधार है जहाँ से कृषि संरचना और कृषि ऋण व्यवस्था के पारस्परिक संबंध को समझा जा सकता है।

समग्र रूप से करनाल मंडल की कृषि संरचना बहुआयामी, मिश्रित और निवेश उन्मुख है। इसमें जोतों की विविधता, गेहूँ–धान प्रधान फसल प्रतिरूप, बासमती आधारित व्यावसायिक संभावना, आधुनिक तकनीकों का उपयोग, बढ़ती लागत, पूँजीगत आवश्यकताएँ तथा जोखिम की उपस्थिति–सभी तत्व एक साथ कार्य करते हैं। यह संरचना क्षेत्र को कृषि दृष्टि से सशक्त बनाती है, परंतु साथ ही वित्तीय निर्भरता और संरचनात्मक चुनौतियों को भी जन्म देती है। अतः करनाल मंडल की कृषि संरचना को समझना कृषि विकास, कृषक वर्गों की स्थिति तथा संस्थागत ऋण व्यवस्था की प्रासंगिकता को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

7. उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों का विश्लेषण

7.1 भारत में कृषि ऋण का व्यापक संदर्भ

भारत सरकार के वित्तीय स्रोतों के अनुसार, पिछले दशक में ग्राउंड लेवल कृषि ऋण लक्ष्य एवं वितरण में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। 2014–15 में कृषि ऋण लक्ष्य 8 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024–25 में बढ़कर 27.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया। यह विस्तार केवल बैंकिंग विस्तार का परिणाम नहीं, बल्कि कृषि में बढ़ती पूँजी–आवश्यकता, केसीसी व्यवस्था के प्रसार, संबद्ध गतिविधियों पर बल, तथा ग्रामीण वित्तीय समावेशन अभियानों का संयुक्त परिणाम है।

तालिका 1: भारत में कृषि ऋण लक्ष्य एवं वितरण का दशकवार परिदृश्य (2014–15 से 2024–25)

वर्ष	कृषि ऋण लक्ष्य/वितरण	राशि	टिप्पणी
2014-15	GLC लक्ष्य	₹ 8.00 लाख करोड़	दशकीय तुलना के लिए आधार
2019-20	वास्तविक वितरण	₹ 13.92 लाख करोड़	पाँच-वर्षीय श्रृंखला का प्रारम्भिक बिन्दु

2021-22	वास्तविक वितरण	₹ 18.63 लाख करोड़	लक्ष्य ₹ 16.50 लाख करोड़; उपलब्धि 113 प्रतिशत
2022-23	वास्तविक वितरण	₹ 21.55 लाख करोड़	कृषि ऋण में तीव्र विस्तार
2023-24	वास्तविक वितरण	₹ 25.48 लाख करोड़	औसत वार्षिक वृद्धि 13 प्रतिशत+ (दशकीय संदर्भ)
2024-25	GLC लक्ष्य	₹ 27.50 लाख करोड़	संबद्ध गतिविधियों हेतु ₹ 4.20 लाख करोड़ उप-लक्ष्य

स्रोत टिप्पणीः भारत सरकार, वित्तीय सेवाएँ विभाग एवं PIB आधारित संकलन.

7.2 हरियाणा में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के ऋण का हालिया परिदृश्य

हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में बैंकिंग प्रदर्शन संतोषजनक रहा, यद्यपि उपलब्धि अनुपात समयावधि और रिपोर्टिंग–कटऑफ के अनुसार बदलता है। 2023–24 में सितंबर तक कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का प्रो–राटा लक्ष्य ₹49,075 करोड़ था, जिसके विरुद्ध उपलब्धि ₹45,294 करोड़ (92 प्रतिशत) रही। 2024–25 में दिसंबर तक प्रो–राटा लक्ष्य ₹76,367 करोड़ था, जिसके विरुद्ध उपलब्धि ₹65,794 करोड़ (86 प्रतिशत) रही।

तालिका 2: हरियाणा में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के ऋण का लक्ष्य एवं उपलब्धि विश्लेषण

वर्ष	रिपोर्टिंग अवधि	प्रो-राटा लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
2023-24	30 सितंबर 2023 तक	₹ 49,075 करोड़	₹ 45,294 करोड़	92 प्रतिशत

2024-25	दिसंबर 2024 तक	₹ 76,367 करोड़	₹ 65,794 करोड़	86 प्रतिशत

स्रोत टिप्पणीः हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 तथा 2024–25.

7.3 करनाल मंडल के लिए उपलब्ध जिला–स्तरीय हालिया संकेत

एसबीआई–विशिष्ट जिला–वार समय–श्रृंखला उपलब्ध न होने की स्थिति में, करनाल मंडल के जिलों के लिए हालिया केसीसी–औपचारिक कृषि ऋण पहुँच संकेत उपयोगी तुलनात्मक आधार प्रदान करते हैं। उपलब्ध जिला–स्तरीय संकलन के अनुसार 2023 से 2024 के बीच करनाल में केसीसी खातों में 36.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि बकाया राशि में 5.91 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। इसका अर्थ यह हो सकता है कि खाते बढ़े हैं, पर औसत ऋण–गहराई दबाव में आई है। कैथल और कुरुक्षेत्र में भी खातों की संख्या बढ़ी, पर असाधारण राशि में क्रमशः 4.52 प्रतिशत और 17.9 प्रतिशत की कमी रही। पानीपत अपेक्षाकृत संतुलित स्थिति में दिखता है, जहाँ खाते 6 प्रतिशत और असाधारण 12.4 प्रतिशत बढ़े।

तालिका 3ः करनाल मंडल के जिलों में केसीसी खातों एवं ऋण राशि का तुलनात्मक विश्लेषण (2023–2024)

जिला	केसीसी 2023	केसीसी 2024	प्रतिशत परिवर्तन	असाधारण 2023 (₹ करोड़)	असाधारण 2024 (₹ करोड़)	प्रतिशत परिवर्तन	2024 प्रति खाता (₹)
करनाल	151,708	207,575	+36.8 प्रतिशत	4,700	4,422	-5.91 प्रतिशत	21,307
कैथल	145,564	167,150	+14.84 प्रतिशत	3,981	3,801	-4.52 प्रतिशत	22,736

कुरुक्षेत्र	125,985	151,786	+20.5 प्रतिशत	3,999	3,284	-17.9 प्रतिशत	21,637
पानीपत	78,857	83,629	+6.0 प्रतिशत	1,906	2,143	+12.4 प्रतिशत	25,622

स्रोत टिप्पणीः हरियाणा के जिला–स्तरीय केसीसी–औपचारिक ऋण पहुँच के हालिया संकलित आँकड़ों पर आधारित। यह तालिका करनाल मंडल के लिए तुलनात्मक चित्र देती है, पर यह एसबीआई–विशिष्ट जिला–वार श्रृंखला का विकल्प नहीं है।

7.4 एसबीआई का समष्टिगत कृषि–वित्त संदर्भ

एसबीआई के वार्षिक प्रतिवेदन कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के वित्तपोषण में बैंक की बड़ी भूमिका को रेखांकित करते हैं। 2022–23 में बैंक की कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत असाधारण अग्रिम लगभग ₹2,56,044.09 करोड़ थे, जो 2023–24 में बढ़कर ₹3,02,705.43 करोड़ हो गए। यह लगभग 18.22 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इस प्रकार, भले ही करनाल मंडल का जिला–वार एसबीआई डेटा सार्वजनिक रूप से पूर्ण न उपलब्ध हो, पर समष्टिगत स्तर पर एसबीआई के कृषि–पोर्टफोलियो के विस्तार से यह स्पष्ट है कि बैंक कृषि–वित्त के राष्ट्रीय ढाँचे में केंद्रीय भूमिका रखता है।

तालिका 4: एसबीआई के कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित अग्रिम एवं एनपीए की स्थिति (2022–23 से 2023–24)

वर्ष	एसबीआई कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ असाधारण	सकल एनपीए	एनपीए प्रतिशत	वृद्धि

2022-23	₹ 2,56,044.09 करोड़	₹ 29,587.72 करोड़	11.56 प्रतिशत	-
2023-24	₹ 3,02,705.43 करोड़	₹ 29,169.55 करोड़	9.64 प्रतिशत	+18.22 प्रतिशत असाधारण; एनपीए ratio में सुधार

स्रोत टिप्पणीः एसबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 एवं 2023–24.

8. विश्लेषणात्मक चर्चा

उपलब्ध द्वितीयक आँकड़े एक महत्वपूर्ण पैटर्न प्रस्तुत करते हैं। पहला, कृषि ऋण का समष्टिगत आकार लगातार बढ़ रहा है– राष्ट्रीय स्तर पर भी और एसबीआई के कृषि–पोर्टफोलियो में भी। दूसरा, हरियाणा जैसे कृषि–सघन राज्य में भी उपलब्धि प्रतिशत एकसमान नहीं है; रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार कृषि एवं संबद्ध ऋण का प्रदर्शन 86 प्रतिशत से 92 प्रतिशत के बीच बदलता है। तीसरा, करनाल मंडल के जिलों में खाता आउटरीच और क्रेडिट की गहराई के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है।

करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र जैसे जिलों में केसीसी खातों की संख्या में वृद्धि यह संकेत देती है कि औपचारिक ऋण पहुँच का विस्तार हुआ है। परंतु असाधारण राशि में समान अनुपात की वृद्धि नहीं दिखती। इससे दो संभावित निष्कर्ष निकलते हैंः या तो ऋण का औसत आकार घटा है, या ऋण–नवीनीकरण–पुनर्भुगतान के पैटर्न बदले हैं। नीति की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि केवल खाता–संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहींय कृषि निवेश की वास्तविक लागत के अनुरूप ऋण–सीमा भी आवश्यक है।

पानीपत की स्थिति अपेक्षाकृत अलग दिखाई देती है, जहाँ खातों और असाधारण दोनों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज है। यह संकेत देता है कि वहाँ औपचारिक ऋण पहुँच और ऋण–गहराई

दोनों में समन्वित वृद्धि हुई। इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि मंडल के भीतर जिला–स्तरीय आर्थिक बनावट, फसल–पैटर्न, औद्योगिक–समीपता और बैंकिंग व्यवहार में अंतर ऋण–प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं।

समष्टिगत एसबीआई डेटा यह पुष्टि करता है कि बैंक कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में अपना अनावरण बढ़ा रहा है और एनपीए अनुपात में भी सुधार दिखा है। यह सकारात्मक है, पर स्थानीय स्तर पर प्रश्न यह बना रहता है कि क्या यह वृद्धि छोटे, सीमांत और वास्तविक खेती करने वाले किसानों तक पर्याप्त रूप से पहुँच रही है। करनाल मंडल के संदर्भ में यह प्रश्न विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि यह क्षेत्र उच्च निवेश वाली कृषि का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ ऋण की गुणवत्ता, समयबद्धता और प्रयोजनानुकूलता निर्णायक होती है।

9. सुझाव

1. करनाल मंडल के लिए जिला–वार, बैंक–वार और फसल–वार कृषि ऋण डेटा का एक सार्वजनिक, वार्षिक और मानकीकृत डैशबोर्ड विकसित किया जाना चाहिए।

2. एसबीआई तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों को केसीसी खातों की संख्या के साथ–साथ प्रति–खाता पर्याप्त ऋण–सीमा पर भी ध्यान देना चाहिए, विशेषकर उन जिलों में जहाँ हिसाब किताब बढ़ रहे हैं पर असाधारण घट रहा है।

3. छोटे और सीमांत किसानों के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और स्थानीय भाषा–आधारित बनाया जाए।

4. गेहूँ–धान प्रधान क्षेत्र होने के कारण करनाल मंडल में जल–संरक्षण, फसल–विविधीकरण और संबद्ध गतिविधियों (डेयरी, बागवानी, प्रसंस्करण) के लिए अलग ऋण उत्पाद विकसित किए जाएँ।

5. कृषि ऋण की समीक्षा केवल वितरण–लक्ष्य के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक उपयोग, आय–प्रभाव, निवेश–परिणाम और पुनर्भुगतान–सुविधा के आधार पर की जानी चाहिए।

6. विश्वविद्यालयीय शोध के लिए जिला लीड बैंक कार्यालयों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति हरियाणा और आरबीआईध्डीएफएस के स्रोतों से विस्तृत पुरालेखीय डेटा प्राप्त कर 2011–2024 की पूर्ण एसबीआई–जिला–वार श्रृंखला तैयार की जानी चाहिएय यह इस विषय पर आगे के अनुसंधान का महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है।

10. निष्कर्ष

करनाल मंडल की कृषि संरचना और संस्थागत कृषि ऋण के बीच गहरा, संरचनात्मक और द्विपक्षीय संबंध है। इस मंडल की कृषि जितनी अधिक सिंचित, तकनीकी और बाजारोन्मुख हुई है, उतनी ही उसकी निर्भरता औपचारिक वित्त पर बढ़ी है। इस संशोधित शोध–पत्र से यह स्पष्ट होता है कि कृषि ऋण का प्रश्न केवल ऋण–वितरण का प्रश्न नहीं, बल्कि कृषि–स्थिरता, किसान–समावेशन, उत्पादन–क्षमता और ग्रामीण सामाजिक न्याय का प्रश्न भी है। उपलब्ध हालिया द्वितीयक आँकड़े बताते हैं कि औपचारिक ऋण पहुँच में विस्तार हुआ है, पर खाता विस्तार और उधार की क्षमता के बीच संतुलन अभी भी चुनौती बना हुआ है। इसलिए नीति–निर्माताओं, बैंकों और शोधकर्ताओं को करनाल मंडल जैसे कृषि–सघन क्षेत्रों में अधिक सूक्ष्म, जिला–विशिष्ट और किसान–श्रेणी आधारित वित्तीय हस्तक्षेप विकसित करने होंगे। यही इस अध्ययन का केन्द्रीय संदेश है।

संदर्भ सूची

प्रेस सूचना ब्यूरो। (31 जनवरी 2025)। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए जमीनी स्तर पर कृषि ऋण वितरण 19.28 लाख करोड़ तक पहुँचा, जिसमें संबद्ध गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया।

कौर, जी., और सिंह, एस. (2018)। करनाल मंडल के किसानों पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रभाव। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 37(3), 211–228।

मलिक, डी. पी., और सिंह, एस. (2015)। हरियाणा में कृषि का विविधीकरणः संस्थागत वित्त की भूमिका। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, 29(2), 102–115.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। (2024–25)। वार्षिक रिपोर्ट 2024–25। भारत सरकार।

वित्तीय सेवा विभाग। (2022–23)। वार्षिक रिपोर्ट 2022–23। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

वित्तीय सेवा विभाग। (2024–25)। वार्षिक रिपोर्ट ६ जमीनी स्तर पर कृषि ऋण पर आधिकारिक विज्ञप्तियाँ। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

हरियाणा सरकार। (2023–24)। हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार।

हरियाणा सरकार। (2024–25)। हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार।

हरियाणा सरकार। (2024)। हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24। आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग।

भारद्वाज, आर. (2019)। कृषि क्षेत्र के वित्तपोषण में भारतीय स्टेट बैंक की भूमिकाः करनाल जिले का एक केस स्टडी। (डॉक्टोरल शोध प्रबंध, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय)।

भारतीय स्टेट बैंक। (2022–23)। वार्षिक रिपोर्ट 2022–23।

भारतीय स्टेट बैंक। (2023–24)। वार्षिक रिपोर्ट 2023–24।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, हरियाणा। (2015)। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, हरियाणा की 131वीं बैठक के एजेंडा और पृष्ठभूमि पत्र।

देवी, आर., और कुमार, एस. (2025)। हरियाणा के किसानों के बीच औपचारिक ऋण तक पहुँच में क्षेत्रीय असमानताएँः एक स्थानिक विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन एंड रिव्यूज, 6(10), 4631–4638।

चहल, वी. पी., और रानी, एस. (2021)। हरियाणा में कृषि ऋण प्रवाह के रुझानः एक क्षेत्रीय विश्लेषण। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, 91(4), 512–517।

चौधरी, एस. (2023)। कृषि ऋण देने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शनः हरियाणा से साक्ष्य। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, 12(1), 89–104।

अरोड़ा, एन., और ज्योति। (2022)। कृषि उत्पादकता पर संस्थागत ऋण का प्रभावः हरियाणा का एक अध्ययन। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, 8(2), 45–58।

गुलाटी, ए., और जुनेजा, आर. (2020)। भारत में कृषि ऋण प्रणालीः विकास और प्रभावशीलता। एकेडमिक फाउंडेशन।

लता, एस. (2016)। हरियाणा में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण का एक अध्ययन, विशेष संदर्भ एसबीआई के साथ। (शोध प्रबंध, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय)।